

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,  
कृषि, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2009


विषय:- वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि वेतन समिति(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रम में राज्य के विश्व विद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतनमान वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 संख्या:169/xxvii(7)/2009 दिनांक 19 जून, 2009 के द्वारा दिनांक 1-4-2009 से पुनरीक्षित किये गये थे। विश्व विद्यालय के कर्मचारी संघ के द्वारा राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 1-1-2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की मांग किये जाने पर कतिपय शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, के वेतनमान दिनांक 1 अप्रैल, 2009 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबद्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विश्वविद्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.03.09 तक के ऐरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.03.09 तक के ऐरियर का भुगतान 3 वर्षों में इस प्रतिबद्ध के अधीन होगा कि समस्त ऐरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।
3. पूर्ववर्ती राज्य में विश्वविद्यालयों के अनुदान को वर्ष 1997 के स्तर पर फ्रीज किया गया था लेकिन नये राज्य के गठन के बाद विश्वविद्यालयों के अनुदान में वृद्धि करके ही प्रत्येक वर्ष बजट व्यवस्था करायी जाती रही है। राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति तथा कर्मचारी संगठनों की मांगों के दृष्टिगत दिनांक 01.01.06 से वेतनमान का पुनरीक्षण किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों को प्राप्त होने वाले शासकीय अनुदान को वित्तीय वर्ष 2009-10 के स्तर पर फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय स्वयं के वित्तीय स्रोतों में वृद्धि कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होकर वार्षिक रूप से स्वायत्तशासी स्वरूप में स्थापित हो सकें।
4. शासनादेश संख्या:169/xxvii(7)/2009 दिनांक 19 जून, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: 256 (1) / xxvii(7) / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार, समस्त विश्व विद्यालय।
5. वित्त नियंत्रक, समस्त विश्वविद्यालय।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उद्यमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं हरिद्वार।
7. सचिवालय के कृषि, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अनुभाग।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
-मा0-  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।